

अपीलान्त

ताराचन्द व अन्य

बनाम

मु.न. 63/2017

रेस्पोडेन्ट्स

ग्राम पंचायत देसूरी व अन्य

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामिल में  
जारी हुये

20/11/2019

वकुलाय उपस्थित।

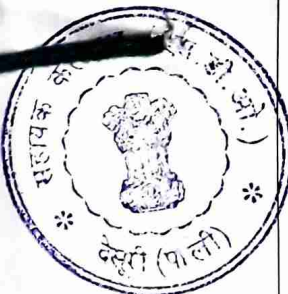
अपीलान्त की ओर से वकील श्री शेषाराम कुमावत उपस्थित तथा रेस्पोडेन्टस संख्या दो से चार की ओर से वकील सुधीर श्रीमाली उपस्थित।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 135(2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दिनांक 09.09.2019 को पेश किया जिसकी प्रति वकील अपीलान्त को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अपीलान्त द्वारा दिनांक 24.10.2019 को पेश किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विधि के आज्ञापक सिद्धान्त अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही मात्र सरसरी व फिस्कल है जिससे किसी व्यक्ति के हक, अधिकार तय नहीं हो सकते हैं। अतः जो अपीलान्त ने 23-24 वर्षों पुराने विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करनी चाही वह विक्रय विलेख प्रथमदृष्टया ही फर्जी व कूटरचित तथा विधि विरुद्ध होने से उनकी चुनौती सक्षम न्यायालय में सिविल न्यायालय देसूरी में सिविल वाद संख्या 1/2018 के विचाराधीन है तथा इसी विवादित आराजी से संबंधित में अपीलान्त स्वयं ने इसी न्यायालय के समक्ष अपने नाम की खातेदारी घोषणा का अनुतोष राजस्व वाद संख्या 56/2017 चुन्नीलाल बनाम ताराचन्द व अन्य में प्रतिवाद/काउन्टर क्लेम के रूप में पेश किया है। जब अपीलान्त की इस अपील का मुख्य आधार के संबंध में ही सक्षम न्यायालयों के उक्त वर्णित अनुसार वाद विचाराधीन है। जिससे दोनों पक्षकारान के हक, अधिकार सक्षम न्यायालयों के निर्णय अनुसार ही सुस्थापित हो सकते हैं। जिससे अपीलान्त की अपील मेन्टेनेबल नहीं हैं। अतः नामान्तरण की कार्यवाही निरस्त फरमावें।

वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अपीलान्त द्वारा पेश कर निवेदन किया कि यह सही है कि नामान्तरण की कार्यवाही मात्र सरसरी व फिस्कल है, जिससे किसी भी व्यक्ति के हक, अधिकार तय नहीं होते हैं किन्तु अपीलान्त द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उनके पिता बंशीलाल की मृत्युपरान्त कत्तई गलत रूपेण प्रश्नगत विरासत नामान्तरकरण दर्ज कराया है, जिसे मंसुख करने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसमें श्रीमान न्यायालय को कोई हक अधिकार तय नहीं करने है अपितु सिर्फ यह देखना है कि मृत बंशीलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी में विद्यमान अपना

सम्पूर्ण हक हिस्सा विक्रय विलेख के जरिये उसके जीवनकाल में उसके स्वयं के द्वारा विक्रय कर दिये जाने से वादग्रस्त आराजी में उनके वारिसान रेस्पोडेन्टस को बतौर वारिसान उत्तराधिकारीगण के



सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपीलान्त  
ताराचन्द व अन्य

बनाम

रेस्पोडेन्टस्  
ग्राम पंचायत देसूरी व अन्य

मु.न. 63/2017

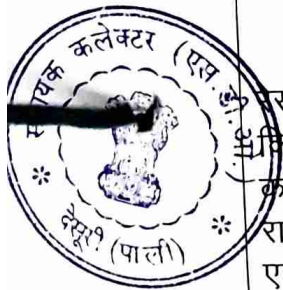
कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होने से रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपने नाम दर्ज कराये अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण दर्ज कराने का अधिकार नहीं होने से विरासत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है या नहीं। इस अपीलान्त की यह अपील किसी प्रकार से धारा 135 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही की परिभाषा में नहीं आती है, जिससे अपीलान्त की यह अपील गलत रूपेण दर्ज किये अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण को निरस्त कराये जाने के संबंध में कानूनन मेन्टेनेबल है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्टस् संख्या दो से चार की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपील का मुख्य आधार के संबंध में ही सक्षम न्यायालयों के उक्त वर्णित अनुसार वाद विचाराधीन है। जिससे दोनों पक्षकारान के हक, अधिकार सक्षम न्यायालयों के निर्णय अनुसार ही सुस्थापित हो सकते हैं। मात्र नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान हक, अधिकार स्थापित नहीं हो सकते हैं। वकील रेस्पोडेन्टस् ने अपनी बहस के समर्थन में फहरिस्त दस्तावेज व निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:-

1. 2010 (1)RRT-310
2. 2006(1)RRT- 473
3. 2006(1) RRT- 633
4. 2011(1) RRT -1264
5. 2009(2)RRT-816
6. 2010(1)RRT-223
7. 2008(2)RRT-1426
8. 2003(2)RRT-753(SC)
9. 2003(2)RRT-870(HC)
10. 2006(2)RRT-923

वकील अपीलान्त की ओर से दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये सिविल एवं राजस्व वाद गलत पेश किये हैं जिनके आधार पर अपीलान्त की अपील किसी प्रकार से कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होना नहीं माना जा सकता है। सिविल एवं राजस्व वादों में निर्णय अनुसार हक अधिकार प्राप्त होंगे। मात्र सिविल एवं राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देने एवं विचाराधीन होने मात्र से अपीलान्त की यह कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होती है। अपीलान्त की अपील कानूनन मेन्टेनेबल है, जो किसी प्रकार की नामान्तरकरण की कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आती है। एवम अपीलान्त की यह अपील कानूनन मेन्टेनेबल है, जिससे अपील की कार्यवाही को स्थागित किया जाना न्याय संगत नहीं है।

उभयपक्षों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस संबंध में वकील रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टान्त सावंतमल व अन्य बनाम तुलची व अन्य 2010 (1)RRT-310 पेश किया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया जिसमें



सहायक कलेक्टर  
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

अपीलान्ट  
ताराचन्द व अन्य

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स  
ग्राम पंचायत देसूरी व अन्य


मु. नं. 63/2017

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह स्थापित किया गया है कि :- "नियमित वाद विचाराधीन है- खातेदारी अधिकार वाद में निर्णीत होंगे।"


अपीलान्ट की इस अपील का मुख्य आधार के संबंध में ही सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। मात्र नामान्तरण की कार्यवाही या नामान्तरण अपील की कार्यवाही के दौरान हक अधिकार स्थापित नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस नामान्तरण की कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित नहीं मानते हैं।

अतः रेस्पोंडेन्ट संख्या दो से चार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में नूटनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ. देसूरी (पाली))

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को सरे-इज्लास में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ. देसूरी (पाली))

